डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 मार्च, 2023, डिस्पेच दिनांक 16 मार्च, 2023

| वर्ष 66 | अंक 20 | भोपाल | 16 मार्च, 2023 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

बहनों का सम्मान बढ़ाने का महायज्ञ है, लाड़ली बहना योजना : मुख्यमंत्री

योजना में 23 से 60 आयु वर्ग की बहनों को प्रति माह एक हजार रूपए दिए जाएंगे

25 मार्च से आवेदन भरना शुरू होंगे, 10 जून को पहली किस्त बहनों के खातों में जमा की जाएगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया योजना का शुभारंभ

योजना के लोगो, ब्रोशर और लघु फिल्म का भी हुआ विमोचन

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाड़ली बहना योजना मेरे दिल से निकली योजना है। बहने सशक्त होंगी तो परिवार, समाज, प्रदेश और देश सशक्त होगा। बहनों के जीवन को सरल, सुखद बनाना ही मेरे जीवन का ध्येय है। बहने अपनी छोटी-मोटी जरूरतों और पैसों की आवश्यकता के लिए परेशान न हो, इसलिए हर महीने बहनों को एक-एक हजार रूपए उपलब्ध कराने की व्यवस्था योजना में की गई है। जिन परिवारों की वार्षिक आय ढाई लाख रूपए से कम है, जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है और जिन परिवारों में कोई आयकर दाता नहीं हो, ऐसे परिवारों की 23 से 60 आयु वर्ग की बहनें योजना के लिए पात्र हैं। योजना में परिवार का अर्थ है, पति, पत्नी और बच्चे। बहनों को यह राशि उपलब्ध कराने से बहनों के साथ पूरे परिवार का भी कल्याण होगा। योजना के लिए 25 मार्च से 30 अप्रैल तक आवेदन भरे जाएंगे। मई माह में आवेदनों की जाँच होगी और 10 जून को पहली किस्त बहनों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। जिन बहनों के बैंक खाते नहीं हैं, उनके खाते खुलवाने में भी मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान भोपाल के जम्बूरी मैदान में विशाल सम्मेलन में योजना का शुभारंभ कर रहे थे। कार्यक्रम से प्रदेश के सभी गाँव तथा वार्ड वर्चुअली जुड़े।

हमारे देश में माँ, बहन, बेटी का हमेशा सम्मान रहा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में महिलाओं को कोई दिक्कत न आए, इसके लिए राज्य शासन द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। हमारे देश में माँ बहन, बेटी का हमेशा सम्मान रहा है। बेटियों और बहनों को हमारे यहाँ दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती माना जाता है। देवता और भगवान के नाम लेने में भी, पहले लक्ष्मी जी और सीता जी का नाम लिया जाता है अर्थात महिला सर्वप्रथम है। कालांतर में परिस्थितियाँ बदली और महिलाएँ भेदभाव का शिकार हो गई।

बहन-बेटियों के लिए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से मेरा मुख्यमंत्री बनना हुआ सार्थक

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बहन-बेटियों के साथ भेदभाव को देखकर मुझे बचपन से ही वेदना होती थी। सार्वजनिक जीवन में सक्रियता के साथ ही मेरा यह प्रयास रहा कि बेटी को बोझ नहीं वरदान समझा जाए। परिणामस्वरूप विधायक बनते ही साथियों के सहयोग से बेटियों का विवाह कराना शुरू किया और मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले कन्या विवाह योजना बना कर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया। मेरा प्रण था कि मध्यप्रदेश की धरती पर जो बेटी पैदा हो वह लखपति हो। इस प्रण से लाड़ली लक्ष्मी योजना ने मूर्त रूप लिया। इसके बाद बेटियों को पढ़ाई में मदद के लिए किताबें, यूनिफार्म, साइकिल आदि की व्यवस्था की गई। मजदूर बहन, बेटा- बेटी के जन्म के बाद आराम कर सके, इसके लिए संबल योजना में जन्म से पहले 4 हजार और जन्म के बाद 12 हजार रुपए देने की व्यवस्था की गई। बहनों के लिए गाँव की बेटी, प्रतिभा किरण और प्रसूति सहायता योजना बनाई गई। बहन-बेटियों को प्रगति के समान अवसर उपलब्ध कराना मेरा सपना था। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वय से मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हुआ।

मुख्यमंत्री ने बहनों का सम्मान कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने आई बहनों का पुष्प-वर्षा कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कन्या-पूजन और बहनों का सम्मान करते हुए दीप जला कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सभी कार्यक्रमों का शुभारंभ कन्या-पूजन के साथ किया जाता है। मैं अपनी बहनों में देवी दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी का रूप देखता हूँ। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ बहनों के सम्मान से किया जा रहा है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

गोहद कृषि उपज मंडी को आदर्श मंडी बनाएँगे : कृषि मंत्री श्री पटेल

भोपाल : किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि गोहद कृषि उपज मंडी को आदर्श मंडी बनाया जायेगा। मंत्री श्री पटेल आज भिण्ड जिले के गोहद में महाराजा भीमसिंह राणा की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे। उन्होंने मंडी को सर्वसुविधायुक्त बनाने के लिये 10 करोड़ की राशि प्रदान करने की घोषणा भी की।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि गोहद कृषि उपज मंडी का नाम अब 'महाराजा भीमसिंह राणा कृषि उपज मंडी' होगा। महाराजा राणा की शौर्य गाथाएँ चिर स्थाई हैं। शौर्य के साथ ही जन-कल्याणकारी कार्यों के लिये वे आज भी हमारी स्मृतियों में अमर हैं।

समारोह में राजस्व, परिवहन और भिण्ड जिले के प्रभारी मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ओ.पी.एस. भदौरिया, सांसद श्रीमती संध्या राय, नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह, विधायक और अन्य जन-प्रतिनिधि शामिल हुए।

लखनऊ में स्टेट हैण्डलूम एक्स-पो में मध्यप्रदेश के उत्पादों की धूम

भोपाल : उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्टेट हैण्डलूम एक्स-पो 2023 में मध्यप्रदेश के उत्पाद आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं। विकास आयुक्त (हाथकरघा मंत्रालय) नई दिल्ली और मध्यप्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा आयोजित इस एक्स-पो का शुभारंभ उत्तरप्रदेश की अपर मुख्य सचिव श्रीमती अनिता भटनागर जैन ने शुभारंभ किया। एक्स-पो 14 मार्च 2023 तक चलेगा। इसमें मध्यप्रदेश सहित 8 राज्यों के बुनकर भागीदारी कर रहे हैं। मध्यप्रदेश की मुख्य कार्यपालन अधिकारी एच.एस.बी.सी. श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि एक्स-पो से मध्यप्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गये खादी-रेशमी वस्त्रों को बाजार मुहैया कराया जा रहा है।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने की विभागीय समीक्षा

भोपाल : सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने मंत्रालय में सहकारिता विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के जमीनी स्तर पर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वयन के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र में दौरा करें और योजनाओं के क्रियान्वयन की सतत निगरानी करें।

समीक्षा बैठक में सहकारिता आयुक्त श्री आलोक कुमार सिंह, एमडी अपेक्स बैंक श्री पी.एस. तिवारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश को विकसित, आत्म-निर्भर बनाने वाला बजट : सहकारिता मंत्री

भोपाल : सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 का मध्यप्रदेश का बजट प्रदेश को विकसित और आत्म-निर्भर बनाने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश की जनता के अनुरूप और उनके हित में बजट दिया है।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि बजट गाँव, गरीब, किसान, विद्यार्थियों, युवा साथियों और मातृशक्ति सहित सभी वर्गों के कल्याण का बजट है। बजट में लाड़ली बहना योजना के लिये 8 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जो प्रदेश की माता-बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त और सक्षम बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। बजट में डिफाल्टर कृषकों के ऋणों के समाधान के लिये सहकारी बैंकों को 1500 करोड़ रूपये की अंशपूँजी, सहकारिता विभाग को 2417 करोड़ 47 लाख रूपये और लोक सेवा प्रबंधन विभाग के लिये 117 करोड़ 78 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। मंत्री डॉ. भदौरिया सहकारिता क्षेत्र में प्रदेश को सशक्त और समृद्ध बनाने के बजट प्रावधानों के लिये मुख्यमंत्री श्री चौहान और वित्त मंत्री श्री देवड़ा का आभार माना है।

खेती और किसानों के लिये लाभकारी है बजट : कृषि मंत्री श्री पटेल

भोपाल : किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि अमृतकाल में प्रस्तुत किया गया प्रदेश सरकार का बजट खेती-किसानी के लिये लाभदायक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि से संबद्ध व्यवसायों के लिये 53 हजार 964 करोड़ और कृषि के लिये 16 हजार 900 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि डिफॉल्टर किसानों का सहकारी समितियों का ब्याज सरकार भरेगी। इसके लिये बजट में ढाई हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। बजट में मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना में 3 हजार 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़, बिजली बिलों पर सब्सिडी के लिए 13 हजार करोड़ सहित किसानों के लिए संचालित अन्य सभी योजनाओं में पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

पहली बार चारे के लिये गौ शालाओं को मिले 202 करोड़ रूपये

पशुपालन मंत्री श्री पटेल ने मुख्यमंत्री का आभार माना

भोपाल : पशुपालन मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल ने बताया कि प्रदेश की पंजीकृत गो-शालाओं में गो-वंश के पोषण के लिये वर्ष 2022-23 में अब तक की सर्वाधिक 202 करोड़ 33 लाख रूपये की राशि प्रदाय की गई है। मंत्री श्री पटेल ने गो-शालाओं के लिए उपलब्ध कराई गई राशि के लिये मुख्यमंत्री और मध्यप्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष श्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। श्री पटेल ने कहा है कि पिछले वर्षों की तुलना में यह राशि कई गुना अधिक है। इससे गो-शालाओं को काफी मदद मिली है और आत्म-निर्भरता में भी वृद्धि हुई है।

मंत्री श्री पटेल ने बताया कि वर्ष 2019-20 में 1583 गो-शालाओं के एक लाख 69 हजार गो-वंश के लिये 41 करोड़ 62 लाख, वर्ष 2020-21 में 1603 गो-शालाओं के 2 लाख 43 हजार गो-वंश के लिये 94 करोड़ 67 लाख, वर्ष 2021-22 में 1630 गो-शालाओं के 2 लाख 76 हजार गो-वंश के लिये 77 करोड़ 89 लाख रूपये और इस वर्ष 1758 गो-शालाओं के 2 लाख 78 हजार गो-वंश के लिये 202 करोड़ 33 लाख रूपये की राशि प्रदाय की गई है। गो-शालाओं में 20 रूपये प्रति गो-वंश दिया जाता है, इसमें 15 रूपये चारा और 5 रूपये सुदाना के लिये शामिल है।

प्रदेश में मुख्यमंत्री गो-सेवा योजना और अशासकीय संस्थानों द्वारा 1758 गो-शालाएँ संचालित कर निराश्रित गो-वंशों का पालन-पोषण किया जा रहा है। गो-शालाओं में गो-काष्ठ, गोबर से गमले आदि बनाने के लिये आर्थिक सहायता भी दी जाती है। गो-शालाओं में जैविक खाद निर्माण, गो-मूत्र औषधि, वर्मीपिट, गोबर गैस प्लांट आदि का निर्माण कर आय के स्रोत भी सृजित किये जाते हैं।

उद्यानिकी कृषकों को चेन फेंसिंग योजना का लाभ जल्द मिलेगा : राज्य मंत्री श्री कुशवाह

भोपाल : उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा है कि उद्यानिकी किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिये शुरू की जा रही खेत चेन फेंसिंग योजना का लाभ जल्द मिलेगा। राज्य मंत्री श्री कुशवाह मंत्रालय में विभागीय समीक्षा कर रहे थे।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि चेन फेंसिंग योजना को शुरू करने की तैयारियाँ की जा रही हैं। उन्होंने माली प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र देने सहित अन्य विभागीय कार्यक्रमों की भी समीक्षा की। संचालक उद्यानिकी सुश्री निधि निवेदिता, महाप्रबंधक एमपी एग्रो श्री संजय गुप्ता और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश के किसानों की उम्मीदों का कृषि बजट

भोपाल : शिवराज सरकार का इस कार्यकाल का आखिरी बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा 1 मार्च 2023 को पेश किया गया। यह बजट किसान, महिला और यूथ पर फोकस हैं।

सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट अमृत काल में विकास और समृध्दि की अमृत वर्षा करेगा। किसानों के लिए समर्पित शिवराज सरकार ने कृषि क्षेत्र में विकास के लिए इस बार कृषि बजट 53 हजार 965 करोड़ रूपये रखा हैं।

2023 बजट में कृषि, बागवानी एवं पशुपालन के लिए किए यह 7 मुख्य प्रावधान

1. **ऊर्जा सब्सिडी:** सरकार ने सिंचाई में विद्युत खपत के लिए 13 हजार करोड़ रूपये सब्सिडी रखी हैं।
2. **मुख्यमंत्री किसान कल्याण:** सरकार ने किसानों को सम्मान निधी के रूप में 4 हजार रूपये प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता के लिए 32,00 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा हैं।
3. **फसल बीमा:** प्राकृतिक आपदाओं से फसल को हुए नुकसान की भारपाई हेतु 2 हजार करोड़ रूपये का बजट रखा हैं।
4. **प्राकृतिक खेती:** यूनिटी मॉल के माध्यम से प्राकृतिक खेती की उपज को बाजार उपलब्ध करायेगी सरकार।
5. **पशुपालन एंव गोसंवर्धन:** सरकार ने पशुपालन एंव गोसंवर्धन आदि के लिए 1 हजार 491 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा हैं।
6. **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना:** सरकार ने मत्स्य पालन के विकास के लिए 97 करोड़ रूपये को बजट में रखा हैं।
7. **प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण:** सरकार ने पैक्स संस्थाओं के कंप्यूटरीकरण के लिए 80 करोड़ रूपये का प्रावधान किया हैं।

राष्ट्रीय बाँस प्रदर्शनी में हरदा जिले के बाँस उत्पादों का प्रदर्शन

भोपाल : म.प्र. राज्य बाँस मिशन ने पीएचडी हाउस, नई दिल्ली में केन्द्रीय किसान कल्याण मंत्रालय की 2 दिवसीय राष्ट्रीय बाँस विकास कार्यशाला एवं प्रदर्शनी में सहभागिता की। मिशन द्वारा हरदा जिले के बाँस उत्पादों का 'एक जिला- एक उत्पाद' के तहत विशेष रूप से प्रदर्शन किया गया। भोपाल के बाँस उद्यमी श्री असित कुमार साहा ने भी अपनी कंपनी फाइन क्राफ्ट इंडिया की बाँस से निर्मित घर की सजावटी वस्तुओं का प्रदर्शन किया।

वन मण्डल हरदा के स्टॉल में बाँस से निर्मित फर्नीचर, टोकरी, लैंप शेड, गुलदस्ते, कोस्टर और गुल्लक जैसे उत्पाद का प्रदर्शन किया गया। पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की कुशल कारीगरी दर्शकों को खूब पसंद आई। फाइन क्राफ्ट इंडिया के स्टॉल में बाँस से बने लैंप, लैंप शेड, डस्टबिन, फाइल फोल्डर और कैरीबैग का प्रदर्शन किया गया।

बाँस उत्पादन में अग्रणी है म.प्र.

मध्यप्रदेश, 3 लाख 85 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में बाँस उत्पादन और 50 मिलियन मीट्रिक टन बाँस भंडार के साथ बाँस क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य है। प्रदर्शनी में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बाँस मिशन भी शामिल हुए।

बाग शिल्पी निभा रहे कला को संरक्षित तथा प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका

ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि-मण्डल ने बाग का भ्रमण कर कला की प्रक्रिया को जाना-समझा

भोपाल : भारत प्रवास पर आए ऑस्ट्रेलिया के 10 सदस्यीय प्रतिनिधि-मण्डल ने धार जिले के छोटे से कस्बे बाग का भ्रमण कर बाग प्रिंट कला की प्रक्रिया तथा बारीकियों को समझा। प्रतिनिधि-मण्डल को बाग प्रिंट कला के उत्पाद बहुत पसंद आए तथा प्रिंटिंग की प्रक्रिया देख कर अभिभूत हो गये। प्रतिनिधि-मण्डल ने बाग प्रिंट के मास्टर शिल्पकार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिल्पियों से चर्चा की तथा बाग प्रिंट प्रक्रिया को भी जाना। दल के सदस्यों ने कहा कि छोटे से कस्बे के शिल्पियों ने अपनी पुस्तैनी बाग कला से देश-प्रदेश का नाम रोशन किया है। बाग शिल्पी विरासत में मिली इस कला को संरक्षित तथा प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि बाग प्रिंट के जनक शिल्प गुरू पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, लाईफ टाईम एचीवमेन्ट और राज्य स्तरीय विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित स्व. श्री इस्माईल खत्री ने इस कला की शुरूआत की थी। आज भी उनकी इस अदभुत कला की विरासत को खत्री परिवार निरंतर सजा-सँवारकर नई ऊँचाइयाँ दे रहा है।

शिल्प गुरू (गोल्ड मेडलिस्ट) राष्ट्रीय हस्तशिल्प,हथकरघा, राज्य स्तरीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित शिल्पकार मोहम्मद युसूफ खत्री ने ऑस्ट्रेलिया के दल के सदस्यों को बाग प्रिंट कला की प्रक्रिया, बारीकियों तथा कला से संबंधित विभिन्न जानकारियों से अवगत कराया। साथ ही उनके पुत्र नेशनल अवार्डी बिलाल खत्री ने भी बाग प्रिंट कला की जानकारी दी तथा ठप्पा छपाई का प्रदर्शन किया। प्रतिनिधि-मण्डल ने कहा की खत्री परिवार के सदस्य दुनिया के सबसे अच्छे शिल्पी होने के साथ ही अच्छे सेल्समैन भी है।

प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्यों को बाग प्रिंट के जनक स्व. श्री इस्माईल खत्री के परिवार के सदस्य शिल्पकार सर्वश्री मोहम्मद रफ़ीक खत्री, उमर फारुख खत्री, मोहम्मद काज़ीम खत्री, मोहम्मद आरिफ खत्री, अब्दुल करीम खत्री, गुलाम मोहम्मद खत्री, कासिम खत्री, अहमद खत्री, मोहम्मद अली खत्री ने भी बाग प्रिंट कला से अवगत कराया। बाग के बिलाल खत्री परिवार ने प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्यों का स्वागत किया। बाग के ट्राइबल फेस्टिवल में विदेशी मेहमान ख़ूब थिरके और आनंद भी लिया।

नवीन खाद्य प्र-संस्करण संस्थान की स्थापना के लिये सलाहकार समिति गठित

भोपाल : उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग अंतर्गत कृषकों को उनकी उपज का समुचित मूल्य प्राप्त हो, इसके लिये नवीन खाद्य प्र-संस्करण संस्थान की स्थापना किये जाने के लिये सलाहकार समिति का गठन किया गया है। समिति का अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण को बनाया गया है।

समिति में प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, प्रमुख सचिव किसान-कल्याण और कृषि विकास सहित राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा विषय-विशेषज्ञ के नामांकित प्रतिनिधि को सदस्य और संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण को सदस्य सचिव बनाया गया है।

सलाहकार समिति संस्थान शुरू किये जाने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। खाद्य प्र-संस्करण संस्थान आने वाले वर्षों में आत्म-निर्भरता एवं निवेश के क्षेत्र में मुख्य भूमिका के रूप में स्थापित होगा।

प्राकृतिक प्रकोप से किसान डरें और घबराएं नहीं, सरकार किसानों के साथ : मंत्री श्री डंग

भोपाल :नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने मंदसौर जिले में प्राकृतिक प्रकोप से हुए फसल नुकसान का खेतों में जाकर औचक निरीक्षण किया। विगत दिवस असमय वर्षा एवं ओला-वृष्टि से फसलों को क्षति पहुँची है।

मंत्री श्री डंग ने किसानों से चर्चा की और कहा कि घबराने और डरने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार, संकट की घड़ी में किसानों के साथ है। सभी किसानों को शासन द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। इस संबंध में प्रशासन को पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सर्वे करवा रहा है। सर्वे के बाद रिपोर्ट के आधार पर सभी को सहायता भी उपलब्ध होगी। किसानों को मदद पहुँचाने में जन-प्रतिनिधि भी लगातार प्रशासन की मदद कर रहे हैं। फसल के क्षति के अवलोकन के दौरान पूर्व विधायक श्री राधेश्याम पाटीदार, स्थानीय जन-प्रतिनिधि और किसान मौजूद थे।

कृषि में श्रेष्ठता हासिल करने के लिए किसान से लेकर इंडस्ट्रीज सब मिलकर काम करें - श्री तोमर

आईसीएआर, कृषि विश्वविद्यालयों व उद्योगों के सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री

नई दिल्ली: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) व इसके तहत आने वाले संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों व उद्योगों का सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर व राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी भी शामिल हुए। सम्मेलन के माध्यम से आईसीएआर का उद्देश्य उद्योग, अनुसंधान एवं शिक्षा जगत के उन संगठनों के साथ काम करना है, जिनकी आईसीएआर की तकनीकों में रूचि है, ताकि पारस्परिक लाभ लेते हुए दीर्घकाल में व्यापकता के साथ कृषि क्षेत्र सहित देश को फायदा मिल सकें।

सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि आईसीएआर ने जो अनुसंधान किया है, उसका उपयोग इंडस्ट्रीज कैसे करें, एक-दूसरे से पूरक होकर इसे कैसे आगे बढ़ाएं, जमीनी स्तर पर काम करने वाली इंडस्ट्रीज क्या चाहती है, फीडबैक मिलेगा तो काम और बेहतर किया जा सकता है। हमारे कृषि उत्पादों की अहमियत दुनिया में बढ़ी है। इस क्षेत्र में जो कमियां है, उन्हें भरने की आवश्यकता है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करते हुए भारत कृषि क्षेत्र में श्रेष्ठता कैसे हासिल कर सकता है, उस दिशा में किसान से लेकर इंडस्ट्रीज, सभी को मिलकर काम करना चाहिए। श्री तोमर ने कहा कि किसान, अनुसंधान, साथ में इंडस्ट्रीज, ये सब आपस में जुड़ते हैं तो इससे अर्थव्यवस्था बलवती होती है, किसान को अपने उत्पादन का वाजिब दाम मिले , इसमें इंडस्ट्रीज का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, आईसीएआर के महानिदेशक डा. हिमांशु पाठक, सम्मेलन की समन्वयक-आईसीएआर की वाणिज्यिक शाखा एग्रीनोवेट इंडिया लि. के सीईओ डा. प्रवीण मलिक सहित उद्योग जगत के प्रतिनिधि श्री हेमेंद्र माथुर व श्री सलिल सिंघल ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखें।

प्राकृतिक कृषि पर कृषकों को किया जागरूक

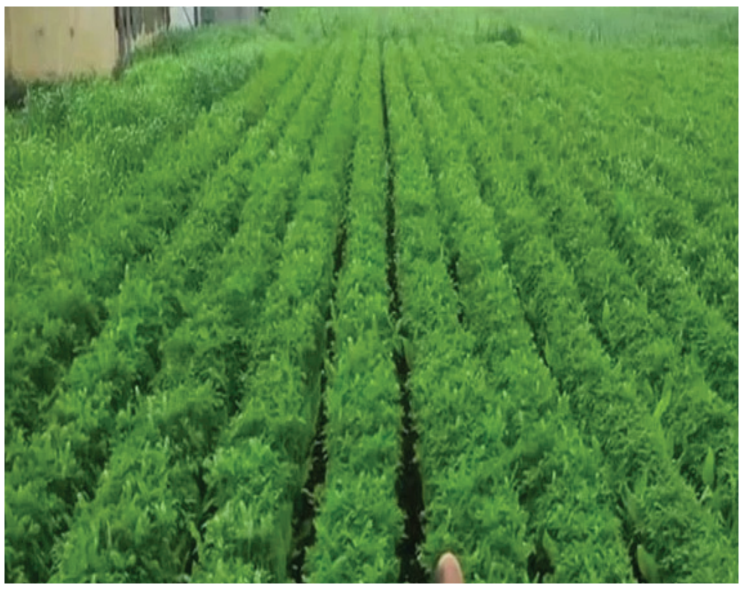

धार। कृषि विज्ञान केन्द्र, धार प्राकृतिक कृषि पर दो दिवसीय कृषक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केन्द्र, धार में ग्राम बगड़ी, विख-नालछा में किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभारी डॉ. जी. एस. गाठिये, सस्य वैज्ञानिक ने बताया कि प्राकृतिक कृषि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत सरकार, नई दिल्ली की महत्वाकांक्षी परियोजना है। प्राकृतिक कृषि को आज की आवश्यकता बताते हुए कहा कि मानव स्वास्थ्य पूर्ण रूप से मृदा के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। उन्होनें कृषकों को प्राकृतिक कृषि की शुरूआत करने की बात कही। श्री डी.एस. मण्डलोई, कार्यक्रम सहायक, ने उद्यानिकी फसलों में प्राकृतिक कृषि के विभिन्न अवयवों के प्रयोग करने की तकनीकी से कृषकों को अवगत कराया। श्री भूपेन्द्र कुमार कुर्मी ने मृदा की विद्युत चालकता, पी.एच. मान एवं उर्वरता के संबंध में कृषकों को जागरूकता करते हुए कहा कि फसल के बेहतर उत्पादन के लिए मृदा में विद्युत चालकता एवं पीएच मान की उपयुक्त स्थिति होना बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम में 'चाईल्ड फंड' से कु. स्नेहा शर्मा, प्रकाश भंवर उपस्थित रहे।

किसानों को सहकारी बैंकों ने जारी किये 39 लाख 57 हजार केसीसी

सहकारिता विभाग की परामर्शदात्री समिति की हुई बैठक

भोपाल : प्रदेश के किसानों को सहकारी बैंकों द्वारा नवम्बर-2022 तक 39 लाख 57 हजार किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा जारी कुल 65 लाख 83 हजार केसीसी में से सहकारी बैंकों की भागीदारी 7 प्रतिशत है। केसीसी से कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण प्रदान किया जाता है। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह जानकारी दी गई। समिति के सदस्य विधायक श्री संजय सत्येंद्र पाठक उपस्थित थे।

सचिव सहकारिता श्री विवेक पोरवाल ने बताया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से समर्थन मूल्य पर गेहूँ का उपार्जन और शासकीय उचित मूल्य दुकानों का संचालन सफलता से किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर समितियों द्वारा 46 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ का उपार्जन किया गया। समितियों द्वारा प्रदेश में 16 हजार 452 शासकीय उचित मूल्य दुकानों का संचालन किया जा रहा है। इनसे 119 लाख परिवारों को समय पर राशन वितरित किया जा रहा है।

विभाग द्वारा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण के वितरण में उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की गई है। वर्ष 2022-23 में 14 हजार 699 करोड़ रूपये के ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को को उपलब्ध कराये गये हैं। राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंकों में बैंकिंग सेवाओं का उन्नयन किया जा रहा है। प्रदेश के 29 जिला सहकारी बैंकों से संबद्ध शाखाओं और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में 4 हजार माइक्रो एटीएम स्थापित किये जा रहे हैं। इनसे समिति स्तर पर किसानों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही राज्य सहकारी बैंक और खरगोन, इंदौर एवं विदिशा जिला सहकारी बैंक में मोबाइल बैंकिंग की सुविधा संचालित की जा रही है।

उपार्जन कार्यों की समीक्षा

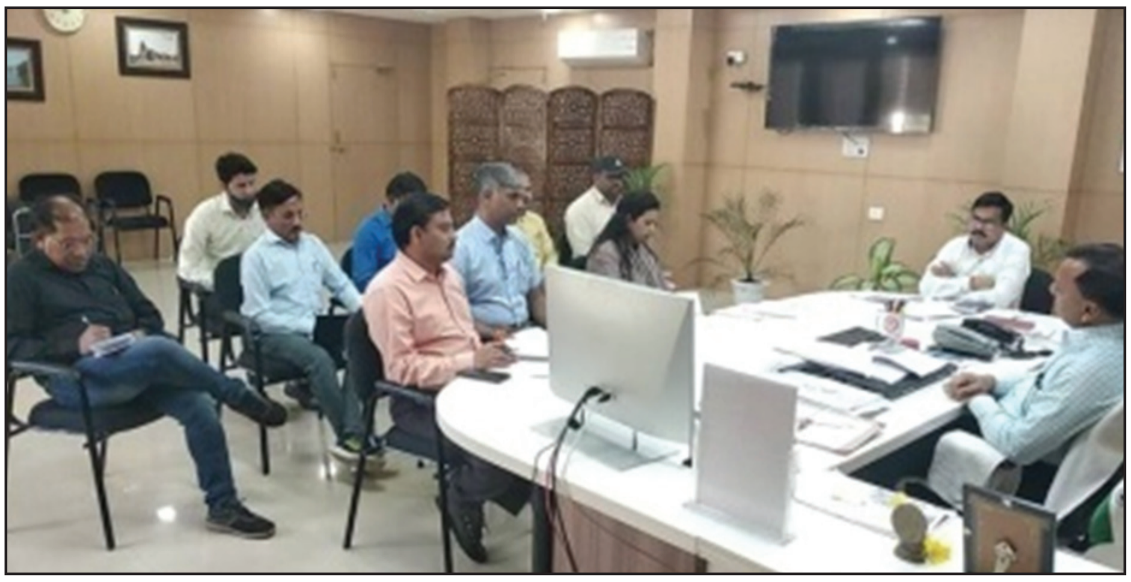

विदिशा : कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने उपार्जन कार्यों की समीक्षा की। उक्त बैठक में बताया गया कि जिले में लगभग छह लाख मैट्रिक टन गेंहू तथा चना, मसूर, सरसों का एक लाख मैट्रिक टन समर्थन मूल्य पर उपार्जन केन्द्रों पर क्रय करने की संभावना है।

कलेक्टर श्री भार्गव ने जिले में करीब सात लाख मैट्रिक टन उपार्जन के लिए किए जाने वाले प्रबंधों के संबंध में आवश्यक निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए हैं उन्होंने कहा कि जिले में गेंहू उपार्जन के लिए वारदाना 26 हजार आठ सौ गठाने की आवश्यकता होगी जबकि जिले में 19 हजार 52 गठाने उपलब्ध है शेष अन्य वारदानो के प्रबंध उपार्जन कार्य शुरू होने से पहले सुनिश्चित हो। इसी प्रकार उन्होंने चना, मसूर के लिए चार हजार गठाने, सरसो के लिए पृथक से वारदानो की उपलब्धता पर बल दिया है।

कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि उपार्जन कार्य वेयर हाउस गोदामों पर ही सम्पन्न होगा। जिसमें सबसे पहले शासकीय गोदामो में भण्डारण का कार्य किया जाएगा। उन्होंने उचित मूल्य दुकानो के माध्यम से वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों के लिए नजदीक के गोदामो में ही भण्डारण पर बल दिया है ताकि परिवहन संबंधी समस्याओं का सामना ना करना पडें। गेंहू, चना की खरीदी कार्य संयुक्त रूप से एकीकृत केन्द्र पर ही की जाएगी।

कलेक्टर श्री भार्गव ने उपार्जन कार्यो के दौरान उपयोग में लाये जाने वाले धागा, स्याही, स्टेनशील इत्यादि की पूर्ति समय सीमा में हो इसके लिए आवश्यक टेण्डर प्रक्रिया शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश कॉ-आपरेटिव बैंक के सीईओ को दिए है।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री अनिल डामोर के अलावा जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू, कॉ-आपरेटिव बैंक के सीईओ श्री विनय प्रकाश सिंह, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री केएस खपडिया के अलावा नागरिक आपूर्ति निगम, मार्कफेड, सहकारिता उपायुक्त मौजूद रहें।

श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का लाभ लेने की अपील

राजगढ़ : असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के समस्त असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हजार से कम है, इस योजना के लिए पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों को प्रतिमाह 55 से 200 रूपये प्रीमियम के रूप मे जमा करना होगा एवं उतनी ही राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा जमा की जाएगी जिसमें 50 प्रतिशत प्रीमियम की राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी। श्रमिक की 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर बीमित व्यक्ति को 3 हजार प्रतिमाह रूपए पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। इस योजना के संचालन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिकृत किया गया है। इस योजना के लिए इच्छुक श्रमिक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (कियोस्क) पर जाकर अपना नामांकन करा सकते हैं । नामांकन के समय श्रमिक को आधार कार्ड एवं बैंक खाता नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा। प्रीमियम की प्रथम किश्त श्रमिक के आयु वर्ग के अनुसार 55 से 200 रूपये कॉमन सर्विस सेंटर में नगद जमा की जाएगी।

महिला कर्मचारियों को 7 दिवस का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश मिलेगा

सीहोर : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश की सभी माताओं-बहनों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ट्वीट कर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला कर्मचारियों को 7 दिवसों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने के साथ बहन-बेटियों के उत्थान के लिए अनेक निर्णय लिये हैं। कक्षा 10वीं के बाद उच्चतर माध्यमिक एवं कॉलेज में बेटियों को वित्तीय साक्षरता हेतु पाठ पढ़ाया जायेगा, जो महिला उन्मुखी होगा। उन्होंने कहा कि माता, बहन और बेटियों का उत्थान ही मेरे जीवन का प्रमुख ध्येय है। नारी शक्ति के सशक्तिकरण में ही प्रदेश और देश का उत्थान निहित है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिलायें आज हर कार्यक्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, पर उन पर मातृत्व और घर संभालने की ज़िम्मेदारी भी है। इसलिए हमने तय किया है कि हम सभी महिला कर्मचारियों को 7 दिवसों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देंगे, जिसे वे अपनी आवश्यकता अनुरूप उपयोग कर सकेंगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य की तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं को रोजगार दिलवाने के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा और जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे। राज्य की तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं को डिजिटल व वित्तीय लिटरेसी, अंग्रेजी, कम्युनिकेशन और वर्क रेडीनेस का 60 से 80 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बालिकाओं को स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें हैंडलूम, कढ़ाई, पारंपरिक लोक कलाओं की ट्रेनिंग सम्मिलित होगी। प्रदेश की महिला हथकरघा व हस्तशिल्प कारीगरों को एनआईडी व निफ्ट संस्थानों के माध्यम से आधुनिक डिजाइन्स और उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण प्रदान कराया जाएगा।

उचित मूल्य दुकान के लिए अब 17 मार्च तक ऑनलाईन आवेदन

भोपाल : भोपाल जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 17 मार्च 2023 तक किए जा सकेंगे । पात्र संस्थाएं अवकाश के दिवस में भी ऑनलाईन आवेदन कर सकती हैं । पूर्व में ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि 16 फरवरी 2023 थी ।

खाद्य आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती मालाकार ने बताया कि पात्र संस्थाओं से उचित मूल्य दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में नवीन उचित मूल्य दुकान खोलने की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाना है।

श्रीमती मालाकार ने बताया कि हुजूर विकासखंड में उचित मूल्य दुकान विहीन ग्राम पंचायत पाटनिया, समसगढ़, डोब, महाबडिया,छापरी, बिशनखेड़ी, गुराडिया और पिपलियारानी में नवीन शासकीय मूल्य उचित दुकान खोली जानी है। इन ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकान के लिए एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

नेफेड के हस्तक्षेप से प्याज की कीमतें हुई स्थिर; किसानों को मिली राहत

लाल प्याज की कीमतों को स्थिर रखने और किसानों को बड़ी राहत देने में कृषि सहकारी संस्था नेफेड कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।

महाराष्ट्र और गुजरात से नेफेड करीब 50 केंद्रों के माध्यम से लाल प्याज की खरीद कर रहा है, जिसमें महाराष्ट्र में 43 और गुजरात में 7 केंद्र खोले गये हैं।

कृषि सहकारी संस्था ने दावा किया कि नेफेड के हस्तक्षेप से दोनों राज्यों में बाजार कीमतों पर सकारात्मक परिणाम दिख रहा है, जिससे इन राज्यों के प्याज उत्पादकों को काफी फायदा हो रहा है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "नेफेड ने गुजरात में लाल खरीफ प्याज की खरीद 9 मार्च 2023 से शुरू की। कृषि सहकारी के हस्तक्षेप का उद्देश्य राज्य के प्याज उत्पादकों को लाभकारी कीमतों को स्थिर करना है।

गौरतलब है कि हाल ही केंद्र ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) को निर्देश दिया है कि कीमतों में गिरावट की खबरों को देखते हुए वो लाल प्याज की खरीद को बढ़ाने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करें और साथ ही देश भर में फैले खपत केंद्रों तक उन्हें उसी समय भेजने और बिक्री का काम करें। 2022-23 के दौरान प्याज का लगभग 318 एलएमटी उत्पादन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के 316.98 एलएमटी के उत्पादन से अधिक है। निर्यात के साथ-साथ मांग और आपूर्ति में निरंतरता के कारण कीमतें स्थिर रहीं। हालांकि फरवरी के महीने में लाल प्याज की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में जहां औसत दर घटकर 500 -700 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गई। विशेषज्ञ कीमतों में इस गिरावट की मुख्य वजह अन्य राज्यों में उत्पादन में बढ़त को बता रहे हैं जिससे देश के प्रमुख उत्पादक जिले जैसे नासिक से आपूर्ति पर निर्भरता कम हुई है।

प्याज सभी राज्यों में उगाया जाता है, हालांकि देश के कुल उत्पादन में लगभग 43 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ महाराष्ट्र सबसे बड़ा उत्पादक है, मध्य प्रदेश की 16 प्रतिशत, कर्नाटक और गुजरात की 9 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। वर्ष में 3 बार खरीफ, पछेती खरीफ और रबी के दौरान फसल के मौसम में पैदावार प्राप्त होती है।

(पृष्ठ 1 का शेष)

बहनों का सम्मान बढ़ाने का महायज्ञ है...

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शाल तथा पोषण दलिया भेंट कर महिलाओं का सम्मान किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान का बहनों ने तिलक, श्रीफल, शाल, आरती, मिठाई और पुष्प-गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री के सम्मान में अभिनंदन-पत्र का वाचन भी किया गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भरवाया योजना का आवेदन और दी पावती

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रिमोट का बटन दबा कर योजना के लोगो, थीम साँग और ब्रोशर का विमोचन किया। उन्होंने योजना की आवेदन प्रक्रिया पर निर्मित लघु फिल्म भी लाँच की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बहनों को योजना में आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी देने के उद्देश्य से बहन कविता का आवेदन स्वयं भरवाया और उन्हें पावती भी दी। इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि आवेदन के लिए समग्र आईडी नम्बर और आधार नम्बर आवश्यक है। मूल निवासी और आय प्रमाण-पत्र आदि की आवश्यकता नहीं है। श्रीमती मनीषा रैकवार ने लाड़ली बहना योजना के संबंध में अपने विचार रखे। योजना पर नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की गई।

आवेदन के लिए हर गाँव और वार्ड में लगेंगे शिविर

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लाड़ली बहना योजना, बहनों का सम्मान बढ़ाने का महायज्ञ है। बहनों को योजना में आवेदन करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर गाँव और हर वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे और आवेदन भरने में मदद करने के लिए कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के वार्डों में शिविरों की जानकारी पहले से दी जाएगी। बहनें योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी बिचौलिए और दलाल के झाँसे में न आएँ। कोई भी कठिनाई होने पर फोन नम्बर 181 पर सूचना दी जाए।

बहनों की सुरक्षा के लिए बनाई जाएगी "लाड़ली बहना सेना"

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार बहन-बेटियों की सुरक्षा, मान-सम्मान और उन्हें प्रगति के सभी अवसर उपलब्ध कराने दृढ़ प्रतिज्ञ है। बहन-बेटियों को परेशान करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में शराब की दुकान के पास के अहाते बंद किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण की ओर अगला कदम बढ़ाते हुए बहन-बेटियों की सुरक्षा के लिए "लाड़ली बहना सेना" भी बनाई जाएगी। बारहवीं कक्षा में शासकीय शाला में प्रथम आने वाली बेटी को ई-स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी बहन-बेटियों को प्रगति और विकास की प्रक्रिया में सक्रियता से सहभागी होने का संकल्प दिलाया।

जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, वित्त, मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सकलेचा, पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री ऊषा ठाकुर, सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद भदौरिया और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, भोपाल सांसद सुश्री प्रज्ञा ठाकुर, खजुराहो सांसद श्री वी.डी. शर्मा, महापौर श्रीमती मालती राय, विधायकगण और जन-प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में महिलाएँ उपस्थित थे।

रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर (सेन्ट्रल रूल) 1956 के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समाचार पाक्षिक के स्वामित्व तथा अन्य विवरण संबंधित जानकारी

घोषणा फार्म चार (नियम–8)

1.	प्रकाशन स्थल	: मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई–8 / 77 शाहपुरा, भोपाल
2.	प्रकाशन अवधि	: पाक्षिक
3.	मुद्रक का नाम	: **गणेश प्रसाद मांझी** वास्ते– मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई–8 / 77 शाहपुरा, भोपाल
4.	प्रकाशक का नाम	: **गणेश प्रसाद मांझी** वास्ते– मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई–8 / 77 शाहपुरा, भोपाल
5.	सम्पादक का नाम	: **गणेश प्रसाद मांझी** वास्ते– मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई–8 / 77 शाहपुरा, भोपाल
6.	क्या भारतीय नागरिक हैं	: हाँ
7.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के हिस्सेदार या साझेदार हो।	: यह समाचार पत्र मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का हैं।

मैं **गणेश प्रसाद मांझी** एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास से ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

सही / –

दिनांक 16 मार्च 2023

(गणेश प्रसाद मांझी)

प्रकाशक

वैम्नीकॉम: महिला उद्यमियों के लिए "शक्ति" कार्यक्रम का आयोजन

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वैम्नीकॉम ने महिला उद्यमियों के लिए ग्लोबल सिनर्जाइज़र, फ़ार्मस्केप फ़ाउंडेशन और इंडिया एक्सीलरेटर के सहयोग से 10 मार्च 2023 को पुणे में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। वैम्नीकॉम की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, इस कार्यक्रम की रूपरेखा संस्था की निदेशक डॉ. हेमा यादव के मार्गदर्शन में तैयार की गई। इस कार्यक्रम में सॉलिड वेस्ट एंड एजुकेशन फॉर ऑल की जिला अध्यक्ष श्रीमती अनुराधा जैन मुख्य अतिथि थीं। वहीं राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे की निदेशक प्रो. (डॉ.) के.सत्या लक्ष्मी और भारतीय स्टेट बैंक कार्यक्रम की पूर्व डीजीएम श्रीमती अनुराधा कुर्मा सम्मानित अतिथि थीं।

इस मौके पर संगठनात्मक व्यवहार, ईएसजी और स्थिरता, सामाजिक उद्यमिता प्रबंधन, मार्केटिंग-फ्रॉम सोशल लेंस और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जानकारी प्रदान की गई। इसका लक्ष्य नवोदित उद्यमियों को जानकारी प्रदान करना था और शीर्ष 10 चयनित उद्यमियों को 2 मिनट अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करना था।

10 में से 7 महिला उद्यमियों ने प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, स्वास्थ्य और कल्याण पारिस्थितिकी तंत्र, पुनर्चक्रण, कृषि और कृषि व्यवसाय, संस्थान निर्माण-सहकारिता, फैशन आदि पर अपनी पिच डेक प्रस्तुतियां दीं। शीर्ष तीन फाइनलिस्ट मेंटरिंग और फंडिंग सपोर्ट के लिए इंडिया एक्सेलरेटर द्वारा ऑन-बोर्ड किए जाएंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन वैम्नीकॉम परिसर में किया गया था। पैन इंडिया से कुल 52 महिला उद्यमियों और स्टार्ट-अप्स ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

फसल नुकसान की जानकारी टोल फ्री नंबर 18001024088 पर 72 घंटे के भीतर देने की अपील

सीहोर : कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने जिले के सभी किसान भाइयों से ओला, बारिश एवं तेज हवा जैसी प्राकृतिक आपदा से फसलों के नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर तत्काल रिलायंस बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 18001024088 पर देने की अपील की है। किसान भाइयों को प्रदाय की गई "आपकी पालिसी आपके हाथ" में विस्तृत निर्देश एवं टोल फ्री नंबर दिया गया है। कृपया बीमा कंपनी को तत्काल सूचित करें।

मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय योजना में जनजातीय वर्ग के लिए अंशदान अब 10 प्रतिशत

सीहोर : "मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम'' के रूप में लागू किया है। कार्यक्रम का लाभ अब विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के साथ सहरिया और भारिया को भी मिलेगा। इन जनजातियों की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए हितग्राही अंशदान की राशि 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये गाय-भैंस प्रदाय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गाय प्रदाय के लिये एक लाख 89 हजार 250 रूपये और भैंस के लिये 2 लाख 43 हजार रूपये की राशि निर्धारित की गई है। 'गौ प्रदाय में एक लाख 70 हजार 325 रूपये शासकीय अनुदान और शेष 18 हजार 925 रूपये हितग्राही अंशदान होगा। भैंस प्रदाय में 2 लाख 18 हजार 700 रूपये का शासकीय अनुदान और मात्र 24 हजार 300 रूपये हितग्राही का अंशदान होगा। हितग्राही को आवेदन निर्धारित प्रपत्र में अपने निकटतम पशु चिकित्सा संस्था या दुग्ध सहकारी समिति को देना होगा। चयन के बाद हितग्राहियों को पशुपालन, पशु आहार और पशु प्रबंधन प्रशिक्षण के साथ परिचयात्मक दौरा भी करवाया जायेगा।

आईटी सेंटर से किसान ले सकते है खसरा और नक्शा की नकल

रायसेन : राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त ने ई-खसरा परियोजना को लागू किया है। जिसके तहत अधीक्षक भू-अभिलेख, तहसीलदार नायब तहसीलदार एवं समस्त पटवारियों की आई.डी. मोडीफिकेशन अपडेशन कार्य हेतु बनाई गई है। परियोजना के अन्तर्गत अनुबंधित फर्म द्वारा सभी तहसीलों में आई.टी. सेन्टर स्थापित किये गये है। जिनसे कृषकों को उनकी मांग अनुरुप प्रमाणित खसरा बी-1, नक्शा की प्रतिलिपियाँ नियत शुल्क प्रति पृष्ठ 30 रुपये लेकर उपलब्ध कराई जा रही है। कृषक अपने खाते की नकल, खेत का अक्श विभागीय बेवसाईट www.mpbhulekh.gov.in पर निशुल्क देख सकता है।

झाबुआ जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

झाबुआ। म. प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर द्वारा माह मार्च 2023 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., झाबुआ के लिये तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिनांक 2 मार्च को प्रधान कार्यालय, पीली कोठी में ''आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश व सहकारिता'' विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमेप की जानकारी दी गई तथा कृषि व सहकारिता के क्षैत्र में आत्मनिर्भर अंर्तगत आने वाली योजनाओं की जानकारी दी गई। बैंक मुख्यालय के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया। बैंक महाप्रबंधक श्री आर. एस. वसुनिया द्वारा राज्य संघ के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सराहना की गई व आगे भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन पर जोर दिया। दिनांक 3 मार्च को शाखा राणापुर व जोबट में 'सायबर अपराध व सुरक्षा उपाय' विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें बैंक में होने वाले सायबर अपराधो के प्रकारो के बारे में बताया गया तथा सुरक्षा उपायो की जानकारी भी दी गई। इस प्रशिक्षण में बैंक शाखा व सम्बद्ध समितियों के कर्मचारियों ने भाग लिया। उन्होंने इस प्रशिक्षण को उनके कार्यक्षेत्र के लिये उपयोगी बताया। इन कार्यक्रमों में विषय संबंधित पाठ्यसामग्री भी वितरित की गई। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर के कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्री शिरीष पुरोहित द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। उनके द्वारा केन्द्र सरकार के नये बने सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहकारिता के हित में किये जा रहे कार्यो की भी जानकारी दी गई।

खरीदी केंद्रों पर समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें : कमिश्नर

नर्मदापुरम : नर्मदापुरम संभाग के तीनों जिले नर्मदापुरम, हरदा एवं बैतूल जिले में सुव्यवस्थित ढंग से रबी उपार्जन कार्य किया जाए। प्रस्तावित खरीदी केंद्रों पर समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। खरीदी की सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाए। यह निर्देश नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर श्री श्रीमन् शुक्ला ने सभी संभागीय एवं जिला उपार्जन संबंधी अधिकारियों को दिए हैं।

कमिश्नर श्री शुक्ला ने कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में आगामी रबी उपार्जन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विस्तार से समीक्षा की। कमिश्नर श्री शुक्ला ने उपार्जन संबंधी अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीदी केंद्रों पर किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखें। केंद्रों पर पेयजल , साफ-सफाई आदि की व्यवस्था रहें। खरीदी के लिए आवश्यक बारदाना सहित अन्य लॉजिस्टिक्स की भी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

कमिश्नर श्री शुक्ला ने बैठक में बैठक में उपार्जन का तुलनात्मक अनुमान, प्रस्तावित उपार्जन केंद्रों की संख्या, किसान पंजीयन में कृषक स्लॉट बुकिंग व्यवस्था आदि बिंदुओ पर समीक्षा की। श्री शुक्ला ने निर्देश दिए कि खरीदी केंद्रों पर शासन द्वारा निर्धारित नॉर्म्स का गंभीरता से पालन किया जाए। व्यवस्थित जांच कर ही संस्थाओं को खरीदी का कार्य सौंपा जाए। रबी उपार्जन की नियमित मॉनिटरिंग करें। अनियमितता करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। किसानों से संबंधित शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए कंट्रोल रूम भी सक्रिय किया जाए।

राशन की कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण लगाएं

कमिश्नर श्री शुक्ला ने बैठक में संभाग के तीनों जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रगति की भी विस्तार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए राशन की कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जाए। राशन वितरण व्यवस्था की निरंतर माइक्रो मॉनिटरिंग करें। कमिश्नर श्री शुक्ला ने दुकान विहीन पंचायतों में दुकान खोलने की कार्यवाही भी शीघ्र करने के निर्देश तीनो जिले के जिला आपूर्ति नियंत्रक को दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री युवाअन्न दूत योजना, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना, एफपीएस का सुदृढ़ीकरण एवं नवीन प्रदाय केंद्र खोलना आदि की भी विस्तार समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। कमिश्नर श्री शुक्ला ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा कर शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

बैठक में संयुक्त आयुक्त श्री जी सी दोहर, संयुक्त संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग श्री बिल्लया सहित खाद्य, सहकारिता, नागरिक आपूर्ति निगम , विपणन संघ आदि विभागों के संभागीय एवं जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

मत्स्य सहकारी समितियों हेतु 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

नौगांव, जिला छतरपुर। म.प्र. राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव एवं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केन्द्र नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 1 मार्च से 3 मार्च 2023 तक मत्स्य सहकारी समितियों का तीन दिवसीय नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम मउ, सहानिया नौगांव, जिला छतरपुर में आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अप्पूराजा सोनी, सरपंच प्रतिनिधि एवं अन्य अतिथि गणों द्वारा दीप प्रज्जवलन कर मां सरस्वती देवी के फोटो पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि श्री अप्पू राजा सोनी द्वारा मत्स्य सहकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी एवं सदस्यों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया साथ ही सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व को आवश्यक बताया और कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन संस्थाओं द्वारा किया जाना अनिवार्य है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री एस. के. साहू , मत्स्य निरीक्षक द्वारा मत्स्य बीज, मछली पालन का मुख्य आहार, मछलियों के रोग, लक्षण एवं उपचार पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, नौगांव के प्राचार्य श्री व्ही.के. बर्वे द्वारा मत्स्य के क्षेत्र में सहकारिता का महत्व, रिकार्ड संधारण, व्यवसाय विकास योजना, निर्वाचन प्रक्रिया/आडिट, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रमुख प्रावधान, सहकारी प्रबंधक/नेतृत्व विकास, कार्यकारिणी कमेटी की बैठकें, कार्यवाही आदि पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, नौगांव के जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक श्री हृदेश कुमार राय एवं श्री बाबूलाल कुशवाह द्वारा सहकारिता का अर्थ, महत्व, सहकारिता के सिद्धान्त, आमसभा की बैठके बुलाने की विधा, कार्यवाही एवं शासकीय योजनाओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को व्यवहारिक अध्ययन भ्रमण हेतु जगतसागर तालाब में मत्स्य आखेट, उसके रख–रखाव एवं क्रय विक्रय से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। तत्पश्चात सहकारी समितियों के अध्यक्षों द्वारा समस्याओं का समाधान विशिष्ट अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सहकारिता विभाग/मत्स्य विभाग/सहकारी बैंक एवं मत्स्य सहकारी समितियों एवं केन्द्र के श्री एन.पी. दुबे, श्री खुबचन्द नाई, का सहयोग सराहनीय रहा।

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के लिए आवेदन 24 मार्च तक

रायसेन : स्व-रोजगार अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत पात्र युवाओं को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के द्वारा वाहन के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराकर प्रदाय केन्द्रों से शासकीय उचित मूल्य दुकानों तक राशन सामग्री का परिवहन कराने के लिए विभागीय पोर्टल samast/mponline.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन 24 मार्च 2023 तक आमंत्रित किए गए है। उक्त योजना के संबंध में जानकारी विभाग के पोर्टल http://food.mp.gov.in एवं samast/mponline.gov.in पर उपलब्ध है। पोर्टल पर प्रदर्शित निर्देशों/जानकारी के अनुरूप पात्र हितग्राही उक्तानुसार पोर्टल पर 24 मार्च 2023 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के गोदाम प्रभारियों हेतु (एम.आई.एस.) आई.एफ.एस.एस. पोर्टल का संचालन विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

भोपाल। श्री ऋतुराज रंजन प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल के जिलो में कार्यरत गोदाम प्रभारियों हेतु "(एम.आई.एस.) आई.एफ.एस.एस. पोर्टल पर उर्वरक एवं भण्डारण व्यवसाय का संचालन" विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 से 28 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में विषय की सारगर्भिता को दृष्टिगत रखते हुए अतिथि वक्ताओं के द्वारा (एम.आई.एस.) आई.एफ.एस.एस. पोर्टल के संचालन के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल से श्रीमति मंदिरा लोधी, डी.जी.एम.आई.टी., श्री नितेन्द्र सिंह, मैंनेजर आई.टी, श्री सौरभ गुप्ता, प्रोग्रामर, श्री शैलेन्द्र सिंह, साफ्टवेयर कन्सलटेन्ट, श्री उमेश बोन्डे, प्रोग्रामर आदि ने पोर्टल से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल के जिलो में कार्यरत गोदाम प्रभारियों को श्री यतीश त्रिपाठी सचिव, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ तथा श्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के द्वारा प्रमाण पत्र का वितरण किया गया।

श्री गणेश प्रसाद मांझी, प्राचार्य, श्री संतोष येडे, राज्य समन्वयक, श्री धनराज सैंदाणे लिपिक, श्री विक्रम मजुमदार, लिपिक, श्री विनोद कुशवाह, प्रशिक्षक के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन श्रीमति मीनाक्षी बान एवं सहयोगी श्रीमति श्रद्धा श्रीवास्तव द्वारा किया गया।

म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा संचालित

(म.प्र. शासन सहकारिता विभाग द्वारा अनुमोदित)

सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम

Higher Diploma in Cooperative Management (HDCM)

माध्यम - ऑनलाईन

योग्यता - स्नातक उत्तीर्ण अवधि - 20 सप्ताह ऑनलाईन आवेदन/प्रवेश की अंतिम तिथि – 31 मार्च 2023

कुल फीस - 20200/-

ऑनलाइन आवेदन / प्रवेश हेतु राज्य संघ के पोर्टल www.mpscuonline.in पर विजिट करें।

संपर्क :-

म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित , भोपाल

ई- 8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल फोन : 0755-2926160 , 2926159

मो. 8770988938 , 9826876158

Website-www.mpscu.in, Web Portal-www.mpscuonline.in

Email-rajyasanghbpl@yahoo.co.in

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र

किला मैदान इंदौर, म.प्र. पिन – 452006

फोन- 0731-2410908 मो. 9926451862, 9755343053

Email - ctcindore@rediffmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र

हनुमान ताल जबलपुर, म.प्र पिन - 482001

मो. 9424782856 , 8827712378

Email - ctcjabalpur@gmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव

जिला छत्तरपुर, म.प्र. पिन – 471201

9424782856 , 9755844511

Email - ctcnowgong@gmail.com

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।